



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 9 मार्च, 2011 / 18 फाल्गुन, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

रामपुर, 29 मई, 2009

सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतु वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतु सूचना

संख्या हिम/एस0डी0टी0पी0/आर0पी0बी0/साडा-सराहन/08-51.—एतद् द्वारा यह सूचना की जाती है कि सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतु वर्तमान भूमि उपयोग तैयार करके दिनांक 19 फरवरी, 2007 को राजपत्र में जनता की आपत्तियों एवं सुझावों हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 12वॉ) की धारा-15 की उप धारा-1 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था। वर्तमान भूमि उपयोग के मानचित्र व रजिस्टर की प्रतियाँ निरीक्षण हेतु सहायक नगर योजनाकार, उप मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, रामपुर, उप-मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर व पंचायत घर, ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु रखी गई थी। जो आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें उपरोक्त विशेष क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र व रजिस्टर में समाविष्ट कर दिया गया है।

अतः वर्तमान भूमि उपयोग की उपरोक्त अधिनियम की धारा-15 की उप धारा-3 के अन्तर्गत संशोधन कर अपना लिया गया है। मानचित्र की प्रतियाँ सहायक नगर योजनाकार, उप मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, रामपुर व उप-मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं।

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतु वर्तमान भूमि उपयोग पर उपरोक्त अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया गया है और इस धारा के प्रभावी होने से कोई भी व्यक्ति/स्थानीय प्राधिकरण, अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर की लिखित अनुमति के बिना न तो वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए गए भू-उपयोग से भिन्न उपयोग को बदल सकता है और न कोई विकास, भूमि उपयोग के विरुद्ध किसी उद्देश्य के लिए कर सकता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी,
रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

**Special Area Development Authority, Sarahan-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushehar, H.P.**

NOTIFICATION

Rampur, the 29th May, 2009

NOTICE FOR ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP/REGISTER OF ADDITIONAL SARAHAN SPECIAL AREA

No.HIM/SDTP/RPB/SADA-Sarahan/08-51.—Notice is hereby given that an existing landuse map / register of additional Sarahan Special Area as prepared and published in Official Gazettee on 19th February, 2007 for inviting public objections and suggestions under Sub-Section (1) of Section-15 of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and copies of the same were placed in the office of Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, Sub-Divisional Magistrate Rampur Office and Gram Panchayat Bhawan Sarahan for inspection. Objections / suggestions so received have been incorporated in the Existing landuse Map/ register of aforesaid Special Area.

The existing landuse is hereby adopted with modification under Sub-Section (3) of Section-15 of Act ibid. Copies of the map/register are available for inspection in the office of Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, Office of Sub-Divisional Magistrate Rampur.

It is hereby notified that the Existing Landuse map of additional Sarahan Special Area is frozen with immediate effect under Section-16 of aforesaid Act, and no person / Local authority shall institute or change use of any land or carryout any development of land for any purpose other

than that indicated in the Existing Landuse map / register of additional Sarahan Special Area without permission in writing of the Chairman, Special Area Development Authority, Sarahan-cum- Sub-Divisional Magistrate, Rampur.

By order,
Sd/-
Chairman,
Special Area Development Authority,
Sarahan-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushehar, H.P.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 फरवरी, 2011

संख्या: सिंचाई 11-68/2010-हमीरपुर.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़ोह तहसील भोरंज जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना बड़ोह में वाटर टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	कनाल/मरले
हमीरपुर	भोरंज	बड़ोह	414 / 1	0-9

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 1st March, 2011*

No.HHC/Admn.16(9)74-VI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Chander Kanta, Advocate as Oath Commissioner at Mandi, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 1st March, 2011*

No.HHC/GAZ/14-259/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant the ex post facto sanction of three days' earned leave w.e.f. 12.11.2010 to 14.11.2010 and seven days' commuted leave w.e.f. 15.11.2010 to 21.11.2010 in favour of Shri Aneesh Garg, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P.

Certified that Shri Aneesh Garg has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Aneesh Garg would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 3rd March, 2011*

No.HHC/Admn.6(24)/74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has

been pleased to confer the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrates Second Class, to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names, with immediate effect :

Sl. No.	Name of the Judicial Officer	Designation and place of posting	District
1.	Sh. Amardeep Singh	Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM (IV), Mandi.	Mandi
2.	Ms. Divya Jyoti Patial	Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM (III), Hamirpur.	Hamirpur
3.	Sh. Sunish Aggarwal	Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM, Solan.	Solan
4.	Sh. Nikhil Aggarwal	Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM (VII), Shimla.	Shimla

By order,
Sd/-
Registrar General

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2011

No.HHC/GAZ/14-319/2010.—Pursuant to the item No. 17 of Himachal Pradesh Government Notification No.Home-B(G)4/95-Vol-III, dated 29.8.2008, three advance increments at the rate of Rs. 770/- per month in the pay scale of Rs. 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 by raising her pay from Rs. 27770/- to Rs. 30010/- are granted in favour of Miss Akshi Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(V), Shimla, *w.e.f.* 21.6.2010.

By order,
Sd/-
Registrar General

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 8 मार्च, 2011

संख्या: वि0स0-वि-बिल / 1-47 / 2011.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हक-चहारूम के संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन के अनुसरण में खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों को हक चहारुम के संदाय की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

एण्डरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 में ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी और लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय में से हुई सकल आय के एक चौथाई भाग, जो उनमें आपस में विभक्त हो, का स्वैच्छिक अनुदान के रूप में संदाय करने का उपबन्ध रहा है;

यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था अपितु यह वन संरक्षण में, उनके हित को सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था;

यह हक-चहारुम प्रणाली, हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात् कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान रही है।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था और ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर 1976 में समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामलात भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित की गई थी;

लम्बरदारों के हक-चहारुम का संदाय, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, 1976 में रोक दिया गया था किन्तु पत्र संख्या: 3-61/69-एस एफ-IV तारीख 10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण वन बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण/सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं;

अतः खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को भूतलक्षी रूप से वर्ष 1974-75 से रोकने/समाप्त कर देने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि वे वन संरक्षण में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम के संदाय का उत्सादन अधिनियम, 2011 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिलों पर होगा।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “हक-चहारुम” से कांगड़ा फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ एंडरसन (1887) के पैरा 61 में यथा उपदर्शित पेड़ों के विक्रय से प्राप्त स्वत्वधारियों अर्थात् खेवटदारों और ग्राम सेवकों अर्थात् लम्बरदारों, पटवारियों और राखों में विभाजित की जाने वाली सकल आय का एक चौथाई भाग (हिस्सा) अभिप्रेत है; और

(ख) "खेवटदार", "लम्बरदार" और "राखा" शब्दों का वही अर्थ और अभिव्यक्ति होगी, जो कांगड़ा घाटी की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में उनकी है।

3. हक-चहारुम प्रणाली का उत्पादन.—हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन राज्य सरकार में शामलात भूमि के विनिधान से खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों का वन संरक्षण में कोई योगदान नहीं रहा है और वे वन संरक्षण के कार्यों और बाध्यताओं से मुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन शामलात भूमि के राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात्, खेवटदार, लम्बरदार और राखे, वन संरक्षण के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं तथा फॉरेस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा वैली के पैरा 61 के अनुसरण में हक-चहारुम के किसी भी प्रकार के संदाय के लिए वे हकदार नहीं होंगे।

4. राखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना.—(1) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने से पूर्व, वनों के संरक्षण और प्रबन्धन की बाबत खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों के समस्त अधिकार, हक और हित सरकार में, समस्त विल्लंगमों से मुक्त, निहित होंगे।

(2) राखों को हक-चहारुम के संदाय की प्रणाली प्रथम अप्रैल, 2010 से उत्सादित (समाप्त) हो जाएगी और वे उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और बाध्यताओं से भार मुक्त हो जाएंगे तथा इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी रिपोर्ट या संविदा, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, खेवटदार और लम्बरदार प्रथम अप्रैल, 1974 से हक-चहारुम के संदाय के हकदार नहीं होंगे, और वे उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और बाध्यताओं से भारमुक्त हो जाएंगे और इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा।

5. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एंडरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी, लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय से सकल आय का एक चौथाई भाग (हिस्सा) प्राप्त होता था, जो उनमें विभाजित होता था। यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता देने के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था, अपितु यह वन संरक्षण में उनके हित सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था। यह हक-चहारुम प्रणाली कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात् धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान थी।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था, जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 11-21/71 (राजस्व-बी) तारीख 1-12-1976 द्वारा हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामलात भूमि सरकार में निहित हुई थी। लम्बरदारों के हक-चहारुम के संदाय को, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 11-21/71 (राजस्व-बी), तारीख 1-12-1976 द्वारा रोकने का विनिश्चय किया गया था, किन्तु पत्र संख्या: 3-61/69-एस एफ-IV, तारीख

10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण, वन-बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज दिन तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त करते रहे हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण या सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं। खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को प्रथम अप्रैल, 1974 से, भूतलक्षी रूप से, समाप्त किया जाना अपेक्षित है। इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधान लाया जाए जो प्रथम अप्रैल, 1974 से भूतलक्षी रूप से हक-चहारुम से संदाय की प्रणाली को समाप्त करने का उपबन्ध करता हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख.....2011

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 2 of 2011

**THE HIMACHAL PRADESH ABOLITION OF PAYMENT OF HAQ-CHUHARAM
BILL, 2011**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for abolition of provision for payment of Haq-Chuharam to Khewatdars, Lambardars and Rakhas pursuant to the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974.

Whereas, under para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari and Lambardar) has got the provision of payment of one-fourth share of the gross income from the sale of trees as voluntary grant, to be divided among them;

And Whereas, this was not a malikana, paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in Forest Conservancy;

And Whereas, this Haq-Chuharam system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts;

And Whereas, the share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post and payment of share of the village communities (Khewatdars) was scrapped in 1976, with the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, vide which village common lands were vested in the Government free from all encumbrances;

And Whereas, the payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also stopped in 1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception in view of letter No.3-61/69-SF-IV dated 10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service in Forest Conservation or protection or to the Forest Department;

Now, therefore, it has been decided to stop/abolish the share of Khewatdars and Lambardars retrospectively from the year 1974-75, because they are not rendering any assistance in forest conservancy.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of the India as follows:—

1. Short title, commencement and extent.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abolition of Payment of Haq-Chuharam Act, 2011.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1974.

(3) It shall extend to the Kangra and Hamirpur Districts of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Haq-Chuharam” means the one-fourth share of the gross income from the sale of trees as indicated in para 61 of the Kangra Forest Settlement Report of Anderson (1887), to be divided among proprietors i.e. Khewatdars and the village servants i.e. Lambardars, Patwaris and Rakhas; and

(b) The words “Khewatdar”, “Lambardar” and “Rakha” shall have the same meaning and expression as assigned to them in the Report on Forest Settlement of the Kangra Valley.

3. Abolition of system of Haq-Chuharam.—With the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, the Khewatdars, Lambardars and Rakhas have been left with no role in forest conservancy and stand relieved of the duties and obligations towards the forest conservation. The Khewatdars, Lambardars and Rakhas are not rendering any service to forest conservation or to the Forest Department after the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, and shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam in pursuance of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra Valley.

4. Vesting of Rights of Rakhas, Lambardars and Khewatdars in the Government.—

(1) All rights, titles and interests of the Khewatdars, Lambardars and Rakhas in respect of conservancy and management of Forests, prior to the coming into force the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, shall stand vested in the State Government free from all encumbrances.

(2) The system of payment of Haq-Chuharam to the Rakhas shall stand abolished with effect from 1st April, 2010 and they shall stand relieved of the duties and obligations attached to them and shall have no liability in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or any report or contract, decree or order of any court, the Khewatdars and Lambardars shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam with effect from 1st April, 1974 and they shall stand relieved of their duties and obligations attached to them and shall have no liability in this regard.

5. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any employees of the Government, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provisions of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari, Lambardar) had got 1/4th share of the gross income from the sale of the trees, to be divided among them. This was not a malikana paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in forest conservancy. This Haq-Chuharam system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts.

The share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post. Further, the payment of share of the village communities (Khewatdars) was scrapped vide letter No. 11-21/71(Rev.B) dated 01-12-1976 with the enforcement of “the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974” vide which village common lands were vested in the Government. The payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also decided to be stopped vide letter No. 11-21/71(Rev.B) dated 01-12-1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception, in view of letter No.3-61/69-SF-IV dated 10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service to forest conservation or protection or to the Forest Department. The share of Khewatdars and Lambardars is required to be scrapped retrospectively from 1st April, 1974. Thus, it has been decided to bring a legislation which may provide for abolition of system of payment of Haq-Chuharam retrospectively *with effect from* 1st April, 1974.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA :
The.....2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 8 मार्च, 2011

संख्या: वि0स0-वि-बिल/1-46/2011.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
 सचिव,
 हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 2 के खण्ड (च) के उप-खण्ड (8) में, “या उपाध्यक्ष” शब्दों के स्थान पर “, उपाध्यक्ष या सदस्य” चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन, अन्यो के अतिरिक्त, जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्षों या उपाध्यक्षों को, लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, “लोक सेवक” के अर्थ के अन्तर्गत लाया गया है। तेरहवें वित्त

आयोग ने यह शर्त अधिकथित की है कि राज्य सरकार इसके स्थान पर या तो एक स्वतन्त्र स्थानीय निकाय लोकपाल की प्रणाली स्थापित करे या स्थानीय निकायों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जांच करने तथा उनके विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए लोक आयुक्त को सशक्त किया जाना चाहिए। इसलिए, उक्त शर्त को पूर्ण करने के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित करने के साथ-साथ उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र का, जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, विस्तार करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख :, 2011

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 1 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (17 of 1983) in clause (f), in sub-clause (8), for the words and sign “or Vice-Chairman”, the signs and words “, Vice-Chairman or Member” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983, besides others, Chairpersons or Vice-Chairpersons of the Zila Parishad and Panchayat Samiti are included in the meaning of “public servant” for inquiring into the complaints against them by the Lokayukta. The 13th Finance Commission have laid down condition that the State Government must put in place either a system of independent local body ombudsmen or the Lokayukta should be empowered to look into complaints of corruption and mal-administration against the members of local bodies and recommend suitable action. Thus, with a view to meet the said condition, it has been decided to amend section 2 of the Act *ibid* and to extend the scope of the said Act to inquire into the complaints against members of the Zila Parishad or the Panchayat Samiti.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister.

SHIMLA :

Dated :....., 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

**DR YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND
FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)**

“GENERAL ADMINISTRATION BRANCH”

NOTIFICATION

Dated: 15th December, 2010

No.UHF.Regr./GA/5-28/2010/-27885-27937.—In exercise of the powers vested under Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987) and with the approval and assent of the Chancellor of Dr. Y.S. Parmar

University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, the Board of Management, Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry is pleased to make the following amendment in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Statutes, 1987.

FORTY SEVENTH AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

(As assented to by the Chancellor [Governor, Himachal Pradesh] vide letter No. 45.3/75-GS-IV dated 06.12.2010).

AN AMENDMENT

To amend the First Statutes of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

(1) This amendment may be called the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987 (Forty Seventh amendment, 2010).

(2) The following amendment shall be made in Statute 5.7(1):

Amendment of Statute 5.7(1):—The existing provision of Statute 5.7(1) shall stand substituted by the following provision: Posts with a minimum of time scale of Rs. 15600 + AGP 8000 (UGC) shall be filled in by direct recruitment. The other posts of Grade 'A' shall be filled in by promotion and direct recruitment in the ratio of 50:50. The posts of Grade 'B' and 'C' shall be filled in by promotion and direct recruitment in the ratio of 75:25 i.e. 75% by promotion and 25% by direct recruitment subject to the condition that quota for promotion from Grade 'D' to the lowest posts of Grade 'C' in any office shall be limited to 25% of the vacancies. The promotions shall, however, be made in accordance with the promotion rules as prescribed.

Provided that in respect of non-teaching administrative and ministerial staff, the posts of Deputy Registrars, Deputy Comptroller, Section Officers, Superintendents, Sr. Private Secretary, Private Secretaries, Personal Assistants, Sr. Assistants, Sr. Scale Stenographers shall be filled in 100% by promotion. However, the post of Assistant Registrar shall continue to be filled in by promotion and direct recruitment in the ratio of 75:25 i.e. 75% by promotion and 25% by direct recruitment from amongst the eligible employees of this University through competitive exam/interview, as prescribed. The post of Junior Scale Stenographers shall be filled in by direct recruitment only. The posts of Clerks falling under Grade 'C' shall be filled in 10% + 20% by promotion from amongst Class IV officials and 70% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The promotion shall, however, be made in accordance with the promotion rules as prescribed by regulations from time to time.

By order,
Sd/-
Registrar.

DR YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)

“GENERAL ADMINISTRATION BRANCH”

NOTIFICATION

Dated: 9th February, 2011

No. UHF.Regr./GA/5-28/2011/- 32123-82.—In exercise of the powers vested under Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act,

1986 (Act No. 4 of 1987) and with the approval and assent of the Chancellor of Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, the Board of Management, Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry is pleased to make the following amendment in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Statutes, 1987.

FORTY EIGHTH AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

(As assented to by the Chancellor [Governor, Himachal Pradesh] vide letter No. 45-3/75-GS-IV dated 29.1.2011).

AN AMENDMENT

To amend the First Statutes of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

(1) This amendment may be called the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987 (Forty Eighth amendment, 2011).

(2) The following amendment shall be made in Statute 5.7(1):

Amendment of Statute 4.6(3):—The existing provision of Note-1 below Statute 4.6(3) shall stand substituted by the following provision: Five non-compounded advance increments shall be given at the time of recruitment to person recruited as Assistant Professor/equivalent on or after 1.9.2008, possessing the degree of Ph.D awarded in the relevant discipline by a University following the process of registration, course-work and external evaluation as prescribed by the University. Persons who hold the M.Phil degree at the time of recruitment on or after 1.9.2008 as Assistant Professor/equivalent shall be given two noncompounded advance increments.

By order,
Sd/-
Registrar.

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-II)

OFFICE MEMORANDUM

Shimla-2, the 9th March, 2011

Subject:—Regarding publication of Notification/Orders in official Gazette.

No.Per(AP.B)D(8)-1/2011.—In continuation of this department O.M. No. Per (AP.B)D(8) 1/2005 dated 15-02-2006 and No. Per(AP.B)B(2)-3/2001 dated 29-05-2006, 19-04-2007, 16-04-2008 and 17-03-2010, on the subject cited above, the undersigned is directed to re-iterate that all the departments will ensure that statutory rules/ orders / regulations are invariably published in the Government Gazette strictly as per the prescribed law without any mistakes and delay. It will also be ensured by the departments that the short title, commencement and year of publication of every Rule should be the same. The Government will seriously view any lapse in this regard.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Personnel).

In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Roshan Lal s/o Late Shri Budhi Ram, r/o Khanwag, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. Shimla (H. P.) ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Whereas Shri Roshan Lal s/o Late Shri Budhi Ram, r/o Vill. Khanwag, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. Shimla has filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter Death date of his mother named Late Smt. Murutu Devi in the Parivar Register in Gram Panchayat Khatnol. The Gram Panchayat Khatnol has stated no objection n to register the names of the applicant vide resolution No. 18 dated 12-3-2011.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of death
1.	Murutu Devi	w/o Late Shri Budhi Ram, r/o Khatnol G. P. Khanwag.	5-4-1980

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of names of the applicant may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Given today 7th march, 2011 under my signature and seal of the court.

Seal.

LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla(R),
District Shimla, Himachal Pradesh.

“निर्वाचन विभाग”

अधिसूचना

शिमला—171009, 9 मार्च, 2011

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:6-7 / 2011-ई.एल.एन., दिनांक 9 मार्च, 2011 को अंग्रेजी रुपान्तर सहित, और भारत सरकार, विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या 451, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 तदनुसार भाद्र 31, 1932 (शक) को केवल अंग्रेजी में तथा अधिसूचना संख्या: 204, दिनांक 3 फरवरी, 2011 तदनुसार माघ 14, 1932 (शक) जो कि प्रवासी निर्वाचक के पंजीकरण के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रुपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से
मनोज कुमार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

“मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य ”

अधिसूचना

9 मार्च, 2011

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2011 से प्रवृत्त हुआ है, द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तःस्थापित धारा 20क के अधीन प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक अर्थात् भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित (दर्ज) नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ भारत में उनका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का हकदार है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जिसने 01-01-2011 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा वह अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का इच्छुक है, को एतद्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उसका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करने के लिए प्ररूप 6क में दावा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों के लिए दिशा-निर्देशों सहित प्ररूप 6क नीचे दिया गया है। प्ररूप 6क में दावा आवेदन सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा प्ररूप 6क तथा दिशा निर्देशों में यथा वर्णित दस्तावेजों सहित भेजा जायेगा। जब दावा आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटोप्रतियों, जो सम्बद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित हों, सहित भेजा जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक अड़सठ निर्वाचन विधान सभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पते वेबसाइट “<http://ceohimachal.nic.in>” पर देखे जा सकते हैं ।

हस्ता/-
मनोज कुमार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh State**NOTIFICATION***9th March, 2011*

Under Rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960. Under Section-20A of the Representation of the People Act, 1950, inserted vide Representation of the People (Amendment) Act, 2010, which has come into effect w.e.f. 10th February, 2011, every overseas elector, i.e., Indian citizen who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to employment, education or otherwise, and has not acquired citizenship of any other country and who is not included in the electoral roll, is entitled to have his/her name registered in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence in India as mentioned in his/her passport is located.

In terms of rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960, every overseas elector whose place of residence in India is located in the State of Himachal Pradesh who has completed 18 years of age as on 01-01-2011, and is desirous of registering his/her name in the electoral roll, is invited hereby to submit claim application in Form-6A for registration in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence as shown in the passport is located. Form-6A alongwith guidelines for the applicants is given below. The claim application in Form-6A may be either submitted in person directly to the registration officer of the constituency concerned or sent to such registration officer by post alongwith the documents mentioned in Form-6A and the guidelines. When the claim application is sent by post, it should be accompanied by photocopies of the relevant pages of the passport duly attested by the competent official of the Indian mission in the country concerned.

Addresses of the registration officers of each of the 68 Assembly constituencies in the State of Himachal Pradesh can be seen on the website “<http://ceohimachal.nic.in>”.

Sd/-
Chief Electoral Officer,
Himachal Pradesh.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—10

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—10



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2010 / भाद्र 31, 1932

No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2010 / BHADRA 31, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 22nd September, 2010/Bhadra 31, 1932 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 21st September, 2010, and is hereby published for general information:—

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ACT, 2010

No. 36 OF 2010

[21st September, 2010.]

An Act further to amend the Representation of the People Act, 1950.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Representation of the People (Amendment) Act, 2010.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

43 of 1950.

2. In the Representation of the People Act, 1950 (hereinafter referred to as the principal Act), after section 20, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 20A.

“20A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen of India,—

Special provisions for citizens of India residing outside India.

(a) whose name is not included in the electoral roll;

(b) who has not acquired the citizenship of any other country; and

(c) who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise outside India (whether temporarily or not),

shall be entitled to have his name registered in the electoral roll in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.

(2) The time within which the name of persons referred to in sub-section (1) shall be registered in the electoral roll and the manner and procedure for registering of a person in the electoral roll under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) Every person registered under this section shall, if otherwise eligible to exercise his franchise, be allowed to vote at an election in the constituency."

Amendment of
section 22.

3. In section 22 of the principal Act,—

(a) after the words "amend, transpose or delete the entry", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted;

(b) in the proviso, after the words "proposed to be taken in relation to him", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted.

Amendment of
section 23.

4. In section 23 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) after the words "direct his name to be included therein", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted;

(b) in the proviso, after the words "strike off the applicant's name in that roll", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted.

Amendment of
section 28.

5. In section 28 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(hh) the procedure for proper verification of facts for amending, transposing or deleting any entry in the electoral rolls, under section 22;

(hhh) the procedure for proper verification of facts for inclusion of or striking off, names in the electoral rolls, under sub-section (2) of section 23;"

V. K. BHASIN,
Secy. to the Govt. of India.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, फरवरी 3, 2011/माघ 14, 1932

No. 204]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2011/MAGHA 14, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2011

का.आ. 244(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2011 है।
(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसको लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) प्रवृत्त होगा।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के उपनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) को पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(खख) “इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में है;”

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गग) “प्रवासी निर्वाचक” से धारा 20क में निर्दिष्ट भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जो अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो;”।

- उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) धारा 20क के अधीन नामावली में सम्मिलित किए जाने के हकदार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक का नाम, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किया जाएगा जो उस स्थान से संबंधित है, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथार्थगणित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है ”।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“8क. प्रवासी निर्वाचकों के रूप में व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस देने की रीति— लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) के प्रारंभ पर और ऐसे अन्य समयों पर जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे, मुख्य निर्वाचन आफिसर, नामावली में प्रवासी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 20क के अधीन प्रवासी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करने वाली एक लोक अधिसूचना जारी करेगा और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार के सभी विदेश स्थित मिशनों को भेजी जाएगी और वह ऐसा प्रचार भी करेगा जिसे वह समीचीन और आवश्यक समझे।

8ख. प्रवासी निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करना—

- (1) प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा निरहित न हो तथा जो उस स्थान से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है, रजिस्ट्रीकृत होने का इच्छुक हो, प्ररूप 6क में संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर को सीधे आवेदन कर सकेगा या डाक द्वारा उसे आवेदन भेज सकेगा।
- (2) नियम 13 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध प्रवासी निर्वाचक के रूप में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि की किन्हीं विशिष्टियों या किसी प्रविष्टि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के संबंध में दावा या आपत्तियों को फाइल करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (3) डाक द्वारा भेजे गए प्ररूप 6क के प्रत्येक आवेदक के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जो संबद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम पदधारी द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित होंगी।
- (4) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्ररूप 6क में प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यपन के लिए उनकी मूल प्रतियां संलग्न की जाएंगी।
- (5) जहां किसी प्रवासी निर्वाचक के रूप में नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए किसी दावे या आपत्ति के संबंध में कोई व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर, यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रयोजन के लिए संबद्ध देश में भारतीय मिशन के किसी पदधारी को पदाभिहित कर सकेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 10 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु जहां ऐसे प्ररूप में प्रवासी निर्वाचकों के नाम अंतर्विष्ट हैं, वहां ऐसी नामावलियों की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएंगी।”।

6. उक्त नियमों के नियम 16 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु जहां कोई दावा या आपत्ति, प्रवासी निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, वहां ऐसे दावों या आपत्तियों की एक सूची उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही ऐसे रूप में, जैसा निर्वाचन आयोग आदेश करे, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी।”।

7. उक्त नियमों के नियम 22 में, उपनियम (1) के खंड (ख) के अंत में आने वाले “और” शब्द के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां किसी नामावली में किसी प्रवासी निर्वाचक का नाम अंतर्विष्ट है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा।”।

8. उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (3) में, “9” अंक के स्थान पर “8क” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
9. उक्त नियमों के नियम 26 के उपनियम (1) में, “6” अंक के पश्चात् “,6क” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

“प्ररूप 8क
(नियम 8ख देखें)

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
..... समा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
..... जिला
..... भारत का राज्य

इस खाने के भीतर पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला (3.5 से.मी.) का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें नीचे मद 1(ज) में प्रस्तुत विशिष्टियों के अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

भाग - क

निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :

- (क) नाम.....
(ख) मध्य नाम.....
(ग) उप नाम.....
(घ) जन्म की तारीख दिन मास वर्ष.
(ङ) लिंग (पुरुष / स्त्री)
(च) जन्म का स्थान -
 (i) ग्राम/नगर.....
 (ii) जिला.....
 (iii) राज्य.....

(छ) पिता / माता/ पति का ब्यौरा

- (i) नाम.....
(ii) मध्य नाम.....
(iii) उपनाम.....

(ज) भारत में मामूली तौर पर निवास का स्थान (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार पूरा पता)

- (i) मकान/गृह सं.....
- (ii) गली/क्षेत्र/ पक्षेत्र/ मोहल्ला/ सड़क.....
- (iii) नगर/ ग्राम.....
- (iv) डाकघर.....
- (v) पिन कोड
- (vi) तहसील/तालुका/मंडल/थाना.....
- (vii) जिला

(इ) पासपोर्ट का ब्यौरा -

- (i) पासपोर्ट संख्या
- (ii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने का स्थान.....
- (iii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने की तारीख.....
- (iv) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के अवसान की तारीख.....

{ उपर मद (क) से (इ) में वर्णित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की - यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो भारतीय मिशन द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें ।}

(ज) वर्तमान निवास के देश के वीजा का ब्यौरा -

- (i) वीजा संख्या
- (ii) वीजा का प्रकार (एकल प्रवेश/बहुविध प्रवेश/ पर्यटक/ कार्य वीजा आदि)
- (iii) वीजा के जारी होने की तारीख
- (iv) वीजा के जारी होने का स्थान.....
- (v) वीजा के अवसान की तारीख
- (vi) जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम

{ उपर उल्लिखित वर्तमान विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की - यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो भारतीय मिशन द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें ।}

2. भारत में मामूली तौर से निवास के स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन.....

(क) भारत में मामूली तौर पर निवास के स्थान से अनुपस्थित होने का कारण - (i) नियोजन/ (ii) शिक्षा/ (iii) अन्य (विवरण दें)

.....

(ख) वह तारीख जिससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहा है ।

.....(दिन/मास/वर्ष)

3. भारत से बाहर के देश का पूर्ण आवासीय पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है,.....

..... ।

4. भारत से बाहर के देश का पूर्ण शासकीय पता जहाँ वह वर्तमान में निवास कर रहा है (नियोजन या शैक्षणिक संस्था, जहाँ वह अध्ययन कर रहा है, के स्थान का पता).....

5. घोषणा - मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार -

- (क) इस आवेदन में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है।
 (ख) मैं जन्म से/अधिवास से/देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ।
 (ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है।
 (घ) किन्तु ऊपर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूँगा, जिसे ऊपर 1(छ) में उद्धृत किया गया है।
 (ङ) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ।
 (च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक् तामील समझी जाएगी, और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता रहूँ।
 (छ) यदि मैं भारत वापस लौटता हूँ और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूँगा।
 (ज) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।
 (झ) इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है।

या
 मेरा नाम.....राज्य के.....निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकेगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान).....
 निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्यांक (यदि जारी किया गया है)..... जारी करने की तारीख

- (ञ) मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है/ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर.....
 स्थान.....
 तारीख.....

387 46/11-2

भाग-ख

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

.....(दिन/मास/वर्ष) को आवेदन प्राप्त हुआ
 श्री/श्रीमती/कुमारी.....का प्ररूप 6क में आवेदन :-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसके नाम को..... (निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. में क्रम सं. पर सम्मिलित कर लिया ।

(ख) नामजूर करने के विस्तृत कारण.....

तारीख.....

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

.....छिद्र.....

भाग - ग

आवेदन की अभिस्वीकृति

(जब व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

प्ररूप 6क में श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता..... का आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख

सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.....
 पता....." ।

[फा. सं. एच-7(18)/98-वि. 2(जिल्द 4)]

एन. कं. मधुश्री, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2750(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा संशोधित किया गया ।

प्ररूप 6क में आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

साधारण अनुदेश

प्ररूप 6क किसके द्वारा भरा जा सकता है

1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. आवेदक ने वर्ष की 1 जनवरी, को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणार्थ, यदि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन 1-1-2011 की अईक तारीख के प्रतिनिर्देश से है, तो आवेदक द्वारा 1-1-2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो।

प्ररूप 6क में आवेदन को कहाँ प्रस्तुत किया जाए

3. आवेदन को उस निर्वाचन क्षेत्र के, जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिए गए अनुसार आवेदक के मामूली निवास का स्थान आता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (इआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्ररूप 6क में आवेदन को इआरओ को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित इआरओ के डाक पते पर भेजा जा सकता है।

[भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के इआरओ की विशिष्टियाँ और डाक पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (<http://eci.nic.in>) पर देखी जा सकती हैं]

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

4. आवेदक के पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला एक हाल ही में खींचा गया आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपकाएँ, जिसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग (अधिमानतः सफेद) की हो।

5. प्ररूप 6क के सभी स्तंभ भरें। विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिए गए अनुसार अपना नाम और अन्य विशिष्टियाँ लिखें।

6. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों और विधिमान्य बीजा पृष्ठांकन अन्तर्विष्ट करने वाले पृष्ठ की फोटो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। ये फोटो प्रतियाँ भारतीय मिशन के किसी सक्षम पदधारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होनी चाहिए। इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिना भेजे गए आवेदन सीधे नामंजूर किए जाने के दायी होंगे।

7. यदि आवेदन को व्यक्तिगत रूप से इआरओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथाउल्लिखित पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सत्यापन के तुरन्त पश्चात् पासपोर्ट को लौटा दिया जाएगा।

मतदान

8. यह उल्लेखनीय है कि आप के नामांकन के पश्चात्, आप निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने में उस समय समर्थ होंगे यदि आप मतदान के दिवस को अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र में स्वयं उपस्थित हैं।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2011

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date on which the Representation of the People (Amendment), Act 2010 (36 of 2010) shall come into force.

2. In the Registration of Electors Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(bb) “Electronic Gazette” shall have the same meaning as assigned to it in clause (s) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(cc) “overseas elector” means a citizen of India referred to in section 20A and who is not less than eighteen years of age on the qualifying date.

3. In rule 5 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely,-

“(3A) The name of every overseas elector who is entitled to be included in the roll under section 20A, shall be included in the part of the roll pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.”

4. After rule 8 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:-

“8A. Manner of giving notice for registration of persons as overseas electors.- On the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 2010 (36 of 2010) and at such other times as the Election Commission may direct, the Chief Electoral Officer may, for the purpose of inclusion of names of overseas electors in the roll, make a public notification requesting every person entitled to be registered as an overseas elector under section 20A and a copy of such notification shall be forwarded to all foreign missions of the Central Government and also make such further publicity as he may consider expedient and necessary.

8B. Inclusion of names of overseas electors in the rolls.-

(1) Every overseas elector, who is not otherwise disqualified for registration and is desirous of being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in his passport

is located, may make an application in Form 6A to the concerned registration officer directly or send the application to him by post.

(2) The provisions of sub-rules (2), (3) and (4) of rule 13 shall *mutatis mutandis* apply for filing of claims or objections to the inclusion of name or to any particulars of an entry or for transposition of any entry from one place to another in the roll as an overseas elector.

(3) Every application in Form 6A sent by post shall be accompanied by copies of all the documents mentioned in the said Form duly attested by the competent official of the Indian Mission in the country concerned.

(4) Every application in Form 6A presented in person to the registration officer shall be accompanied by photocopies of all the documents mentioned in the said Form alongwith originals thereof for verification by the registration officer.

(5) Where a personal hearing is necessary in respect of any claim for inclusion or objection to the inclusion of name in the roll as an overseas elector, the registration officer may, if considered necessary, designate an official in the Indian Mission in the concerned country for the purpose.

5. In rule 10 of the said rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that where such draft contains names of overseas electors, the copies of such rolls shall also be published in the Electronic Gazette.”

6. In rule 16 of the said rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that where any claim or objection relates to registration of a person as an overseas elector, a list of such claim or objection shall be exhibited on the notice board in his office and shall also be published in the Electronic Gazette in such form as the Election Commission may direct.”

7. In rule 22 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (b), before the word “and” occurring at the end, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where the roll contains the name of any overseas elector the same shall also be published in the Electronic Gazette.”

8. In rule 25 of the said rules, in sub-rule (3), for the figure “9”, the figure and letter “8A” shall be inserted.

9. In rule 26 of the said rules, in sub-rule (1), after the figure “6”, the figure and letter “6A” shall be inserted.

10. After Form 6 appended to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:-

387 96711-3

“FORM 6A
(see rule 8B)

Application for inclusion of name in electoral roll by an overseas elector

To

The Electoral Registration Officer,
-----Assembly/Parliamentary
Constituency

District.....
State in India.....

Space for pasting one
recent passport size
photograph
(3.5×3.5CM)
showing frontal view
of full face within
this box

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the Constituency in which my place of residence, as per the particulars furnished below in item 1(h), is located.

PART - A

Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

- (a) Name -
- (b) Middle Name.....
- (c) Surname
- (d) Date of Birth: --- Day---Month---Year
- (e) Sex(Male/Female)
- (f) Place of Birth -
 - (i) Village/Town.....
 - (ii) District.....
 - (iii) State.....
- (g) Father's/Mother's/Husband's detail
 - (i) Name -
 - (ii) Middle Name.....
 - (iii) Surname
- (h) Place of Ordinary Residence in India (Full Address as given in the Passport)
 - (i) House/Door number.
 - (ii) Street/Area/Locality/Mohalla/Road
 - (iii) Town/Village.....
 - (iv) Post Office
 - (v) Pin Code
 - (vi) Tahsil/Taluka/Mandal/Thana.....
 - (vii) District
- (i) Passport Details -
 - (i) Passport Number
 - (ii) Place of Issue of current Indian
Passport

(iii) Date of Issue of current Indian
passport.....

(iv) Date of expiry of current Indian
passport.....

{Copies of the relevant pages of the passport containing the particulars mentioned at items (a) to (i) above to be enclosed—attested by the Indian Mission if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer}

(j) Details of Visa of the Country of current residence—

(i) Visa Number.....

(ii) Type of Visa (Single Entry/Multiple
Entry/Tourist/Work Visa etc.).....

(iii) Date of issue of
Visa.....

(iv) Place of issue of
Visa.....

(v) Date of expiry of
Visa.....

(vi) Name of the Issuing Authority.....

{Copies of the relevant pages of the passport containing the current valid visa endorsement mentioned above to be enclosed—attested by the Indian Mission if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer}

2. Description of Absence from Place of Ordinary Residence in India-

(a) Reason of being absent from the place of ordinary residence
in India- (i) employment/ (ii) education/ (iii) other(Give Description)
.....

(b) Date from which absenting from ordinary residence in
India (DD/MM/YYYY)

3. Full residential address in the country outside India where currently
residing.....

4. Full Official address in the country outside India currently residing (address of
the place of employment or the education institution where studying).
.....

5. Declaration - I hereby declare that to the best of knowledge and belief—

(a) all information given in this application is true.

(b) I am a citizen of India by birth/ domicile/ naturalisation

(c) I have not acquired citizenship of any other country.

(d) But for being absent from the place of my ordinary residence
in India owing to the reason given in 2(a) above, I would
have been ordinarily resident at the address given in my
Indian Passport, which has been reproduced at 1(g) above.

(e) I undertake to immediately inform the Electoral Registration
Officer through the Indian Mission in the Country of my

387 46/11-4

- * current residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.
- (f) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and the rules made thereunder, and that it is my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.
- (g) If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.
- (h) I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.
- (i) My name has not already been included in this or any other constituency.

Or

My name may have been included in the electoral roll of Constituency in State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and, if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll, or transposed, as may be appropriate.

Full address (Earlier place of ordinary residence)

Elector Photo Identity Card (if issued) number
date of issue

- (j) I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for cancellation.

Signature.....
Place.....
Date.....

PART – B

(For use in the office of Electoral Registration Officer)

Application received on (DD/MM/YYYY)

The application in Form 6A of Shri/Shrimati/Kumari.....has been :-

- (a) Accepted and the name has been registered in the electoral roll of
.....(constituency) at S.No..... Part No.....
- (b) Rejected for the reason.....

Date.....

[Electoral Registration Officer].

perforation

PART - C**Acknowledgement for Application**

(When presented in person to the registration officer)

Received the application in Form 6A of

Shri/Shrimati/Kumari

Address

Date

Signature of the Verifying Officer

Address

[F. No. H-7(18)/98-Lcg. II (Vol. IV)]

N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.

Note—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 2750(E) dated the 11th November, 1960 and last amended *vide* number S.O. 1219(E) dated the 15th May, 2009

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6A**General Instructions****Who can file Form-6A**

1. Every citizen of India staying in a foreign country, who has not acquired citizenship of a foreign country, and has completed 18 years of age as on 1st January of the year, can make an application in Form 6A for being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in the passport is located. The application in Form 6A can be presented to the registration officer concerned.

2. The applicant should have completed eighteen years of age as on 1st January of the year. For example, if the application is for inclusion of name in the electoral roll with reference to 01-01-2011 as the qualifying date, the applicant should have completed 18 years of age as on 01-01-2011.

Where to submit the application in Form-6A

3. The application should be submitted directly to the Electoral Registration Officer (ERO) of the constituency within which the place of ordinary residence of the applicant as given in the valid passport falls. The Application in Form 6A can be presented in person to the ERO or sent by post addressed to the ERO concerned.

[The particulars and postal address of the EROs of all the constituencies of India can be seen on the website of Election Commission of India (<http://eci.nic.in>)]

Documents to be attached

4. Paste one recent passport size coloured photograph with a light background (preferably white) showing the full face of the applicant.

5. Fill in all the columns in Form-6A. Write your name and other particulars as given in the valid Indian Passport

6. If application is sent by post, it should be accompanied by photo-copy of the relevant pages of the passport containing the photograph and all other particulars of the applicant and the page containing the valid visa endorsement. **These photo-copies should be got duly attested by the competent official in the Indian Mission.** Applications without the attested photo-copies of these documents will be liable to be summarily rejected.

7. If the application is submitted in person before the ERO, the application should be accompanied by a photo-copy of the relevant pages of the passport as mentioned above. The original passport should also be produced alongwith the application for verification by the registration officer. The passport will be returned immediately after verification.

Voting

9. It may be noted that after your enrolment, you will be able to cast vote in election in the constituency, if you are physically present in the polling station alongwith your original passport on the day of poll.